साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 11-17 मार्च 2024 वर्ष-9, अंक-47

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

» मप्र सरकार ने बिना बोनस के 46 लाख टन धान खरीदा

» अब 100 लाख टन गेहूं के लिए लेंगे 50 हजार करोड़ का कर्ज

धान में 3100 रुपए एमएसपी का वादा और 2,183 में खरीदा

ये कैसी गारंटी! किसानों के साथ छल

» पिछले साल से 14 हजार करोड़ रुपए ज्यादा कर्ज लेगी सरकार

» 2,700 का वादा और 2,275 रु. क्विंटल गेहूं खरीद रही सरकार

» किसान बोले-राज्य सरकार को लोकसभा चुनाव में देंगे जवाब

भोपाल। जागत गांव हमार

गेहूं की खरीदी के लिए इस बार बाजार से 50 हजार करोड़ कर्ज लेने की तैयारी है। यह पिछली बार से 14 हजार करोड़ रुपए ज्यादा है। सरकार की गारंटी के लिए इसका प्रस्ताव कैबिनेट में जाने वाला है। इतनी बड़ी राशि बाजार से उठाने के कारण किसानों ने बोनस की मांग उठा दी है। इसके पीछे बड़ी वजह भी है कि 15 जनवरी को पूरी हुई धान की खरीदी सरकार ने बिना बोनस के कर ली। कुल 46 लाख टन धान 2183 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर खरीदा गया। यानी किसानों को बोनस का 3,758 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। रबी में बोनस नहीं मिलता है तो फिर उन्हें 4250 करोड़ का नुकसान होगा। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के संकल्प पत्र 2023-24 में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर बोनस जोड़कर गेहूं 2,700 रुपए प्रति क्विंटल और धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदने का वादा था। हाल ही में पूरी हुई धान की खरीदी 2,183 रुपए प्रति क्विंटल पर की गई। यानी 817 रुपए प्रति क्विंटल का किसानों को नुकसान हुआ है। वहीं गेहूं का समर्थन मूल्य वर्ष 2024-25 में 2275 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि बाजार में गेहूं का रेट 2500 रुपए चल रहा है।

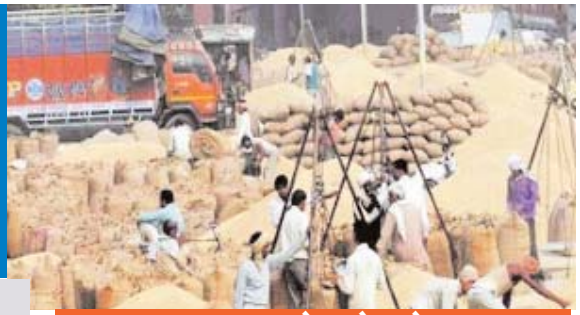

रबी के लिए कब-कितना कर्ज

2023-24	36,000 करोड़
2022-23	29,000 करोड़
2021-22	25,000 करोड़

नोट(गेहूं खरीदी के साथ बारदाने, परिवहन, सिलाई, भंडारण और सोसायटी का कमीशन इसी से होता है।)

कब-कितना गेहूं खरीदा

2023-24	70 लाख टन
2022-23	46 लाख टन
2021-22	129 लाख टन
2020-21	128 लाख टन

नोट: 2020-21 एवं 2021-22

425 रुपए बोनस देना होगा

यही स्थिति अब रबी सीजन के गेहूं की खरीदी की होने वाली है। एमएसपी के बाद सरकार को 425 रुपए बोनस देना होगा। साफ है कि पार्टी के संकल्प पत्र में अनाज खरीदी से जुड़े बिंदु सवालों के घेरे में आ गए हैं। सरकार को यदि बोनस देना है तो इसकी घोषणा जल्द करनी होगी। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाती है तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी।

देश में गेहूं की डिमांड

देश में गेहूं की डिमांड है। इस बार राज्य सरकार ने सर्वाधिक 100 लाख टन (कोरोना के दो साल 2020-21 व 2021-22 को छोड़कर, इन दोनों वर्षों में क्रमशः 128 लाख और 129 लाख टन गेहूं खरीदा गया था, क्योंकि सरकार के अलावा किसी ने खरीदी नहीं की।) गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए बाजार से अब तक की सबसे बड़ी रकम बतौर कर्ज लेना प्रस्तावित है।

सरकार बोनस पर विचार कर रही हैं। जो भी संभव होगा, किसानों के लिए बेहतर करेंगे। सम्मान निधि से लेकर किसानों के हित में सरकार कई योजनाएं पहले से चला रही। बोनस का प्रस्ताव कैबिनेट में ले जाएंगे।

गोविंद सिंह राजपूत, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री

धान का बोनस नहीं दिया। अब गेहूं का तो आदेश सरकार जल्दी जारी करे। अभी तक कोई आदेश नहीं होने के कारण ही हम धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। जब वादा किया है तो बोनस देना चाहिए।

राहुल धूत, प्रांत प्रचार प्रमुख भारतीय किसान संघ

मेनिफेस्टो में जब बोला गया है तो बोनस देना चाहिए। सिर्फ वोट बटोरना गलत है। सरकार की इस अनदेखी से किसानों को आर्थिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अनिल यादव, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन

सरकार ने अपने संकल्प पत्र में किसानों को गारंटी दी कि एमएसपी पर धान 3100 रुपए क्विंटल खरीदी होगी, लेकिन हमें 2183 रुपए क्विंटल के हिसाब से भुगतान किया गया है। इसी तहर सरकार ने कहा था कि गेहूं 2700 रुपए क्विंटल खरीदा जाएगा, लेकिन 2,275 रुपए क्विंटल के मान से रजिस्ट्रेशन हो रहा है।

राघवेंद्र द्विवेदी, प्रगतिशील किसान, मऊगंज

सीएम डॉ. मोहन यादव बोले-भिंड में कृषि संकाय शुरू किया जाएगा

मप्र के किसानों के खाते में डले फसल बीमा के 775 करोड़

भोपाल। जागत गांव मार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भिंड में किसान एवं सहकारिता सम्मेलन में 80 लाख से अधिक किसानों को किसान कल्याण योजना के एक हजार 816 करोड़ रुपए और 25 लाख से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना के 755 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक से अंतरित किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 193 करोड़ 35 लाख रुपए के 68 विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने नयागांव में महाविद्यालय आरंभ करने, गौरी सरोवर तालाब का विकास कर उसका संपूर्ण कायाकल्प करने, मेहगांव को नगर पंचायत बनाने, भिंड के कॉलेज में कृषि संकाय आरंभ करने की घोषणा भी की।

जन-जन के मन में है प्रधानमंत्री मोदी

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की पहल पर गरीबों के बैंकों में खाते खुलवाए गए और हर व्यक्ति का हक उसे सीधे दिलवाने की व्यवस्था स्थापित की गई। इसी का परिणाम है कि किसानों के खातों में किसान कल्याण और फसल बीमा योजना की राशि सीधे अंतरित की गई है। जनकल्याण के भाव को सरलता से क्रियान्वित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अभिनंदनीय हैं।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने की राशि बढ़ाने की घोषणा

मध्यप्रदेश की गौशालाओं को 20 नहीं अब प्रति गाय 40 रुपए देगी राज्य सरकार

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश की सियासत में गाय और गौशाला बड़ा मुद्दा है। देश में भी राजनीतिक रूप से गाय काफी अहम है। दक्षिण को छोड़ दें तो देश के उत्तर और पूर्वी हिस्से में लगभग हर राज्य में गाय को लेकर कोई न कोई योजना है। मध्य प्रदेश सरकार अब हर गौवंश पर 40 रुपए देगी, पहले ये राशि 20 रुपए हुआ करती थी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में गौ-माता और गौ-वंश के संरक्षण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। गौ-शालाओं के बेहतर संचालन के लिए उन्हें दी जा रही राशि में वृद्धि की जाएगी। गौ-रक्षा संवाद निरंतर होता रहेगा। इस विषय पर विचार-विमर्श की प्रक्रिया जारी रहेगी, ताकि गायों और गौ-शालाओं के बेहतर प्रबंधन के उपाय किए जा सकें। प्रदेश में चरनोई की भूमि पर अतिक्रमण हटाने, प्रति 50 किलोमीटर पर सड़कों पर दुर्घटना का शिकार हुई गायों को इलाज के लिए भिजवाने और सड़कों पर बैठने वाले पशुधन को बैठने से रोकने या अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिये आधुनिक उपकरणों की सहायता ली जाएगी। गायों के लिए चारा काटने के उपकरणों पर अनुदान की व्यवस्था की जाएगी। पंचायतों को जरूरी सहयोग और प्रेरणा मिले, इसके लिए गौ-संवर्धन बोर्ड प्रयास करेगा। गायों के लिए गौ-शालाओं को प्रति गाय की राशि 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रदान की जाएगी। अधूरी गौ-शालाओं का निर्माण पूर्ण किया जाएगा। नई गौ-शालाएं भी बनेंगी।

सीएम की प्रमुख घोषणाएं

» प्रदेश में संचालित गौ-शालाओं को श्रेष्ठ संचालन के लिए पुरस्कृत किया जाएगा।

» भारतीय नव वर्ष अर्थात इस चैत्र माह से अगले वर्ष तक वह गौ- वंश रक्षा वर्ष मनाया जाएगा।

» चरनोई की भूमि से अतिक्रमण हटाए जाएंगे। पंचायतों को आवश्यक सहयोग किया जाएगा।

» चारा या भूसा काटने के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरण पर अनुदान की व्यवस्था होगी।

» प्रति 50 किलोमीटर पर ऐसी व्यवस्था होगी कि घायल गाय को इलाज के लिए आसानी से ले जाया जा सके।

» प्रदेश में हाईड्रोलिक कैटल लिफ्टिंग व्हीकल का टोल व्यवस्था के अंतर्गत प्रबंध किया जाएगा।

» अधूरी गौ-शालाओं का निर्माण पूर्ण किया जाएगा। इसके लिए मनरेगा से भी राशि का उपयोग होगा।

» मध्यप्रदेश में नई गौ-शालाएं भी प्रारंभ की जाएंगी। गौ-वंश विहार विकसित किए जाएंगे।

आत्मनिर्भर

गौ-संरक्षण और गौ-सेवा की भावना जन-जन में विकसित करना महत्वपूर्ण

गौ-रक्षा संवाद कार्यशाला का डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने किया शुभारंभ, बोले

प्रदेश में गौ-वंश के बेहतर प्रबंधन से सशक्त अर्थव्यवस्था का निर्माण संभव

भोपाल। जागत गांव हमार

उप-मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि गौ-वंश के बेहतर प्रबंधन से अर्थव्यवस्था को सशक्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गौ-वंश हर वक्त लाभप्रद हैं। दुग्ध और दुग्ध प्रोसेस्ड उत्पादों के साथ, गौ-मूत्र और गोबर से भी कई तरीके उत्पाद बनाए जा सकते हैं जो गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ-वंश का आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक महत्व है। गौ-संरक्षण और गौ-सेवा की भावना जन-जन में विकसित करना महत्वपूर्ण है। उप मुख्यमंत्री ने कुशाभाउ ठाकरे सभागृह भोपाल में गौ-रक्षा संवाद निराश्रित गौ-वंश एवं गौशालाओं के बेहतर प्रबंधन पर हितग्राहियों की कार्यशाला का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि गौशालाओं के प्रबंधन में अधोसंरचना विकास के साथ मानव संसाधन (गौ-सेवक) की व्यवस्था महत्वपूर्ण घटक है। इसके साथ ही विभिन्न उत्पादों के निर्माण और विपणन की बेहतर व्यवस्था गौशालाओं को आर्थिक मजबूती देने के लिए जरूरी है।

रोजगारों का सृजन होगा- उप मुख्यमंत्री ने बसामन मामा गौ-वंश वन्य विहार रीवा में किए जा रहे प्रयासों से उपस्थित जनों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि गौशालाओं के बेहतर प्रबंधन से गौ-वंश का संरक्षण और संवर्धन सुनिश्चित होगा साथ ही रोजगारों का सृजन होगा। उप मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा गौ-सेवा के अभिनव प्रयास के लिए आभार व्यक्त किया।

गौ-सेवा में सहयोगी होंगे सुझाव

पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में कहा कि गौ-रक्षा और गौशालाओं के बेहतर प्रबंधन पर प्राप्त सुझाव, गौ-सेवा में सहयोगी होंगे। उन्होंने कहा कि शासन का लक्ष्य है कि कोई भी गौ-वंश निराश्रित न हो, दुर्घटना का शिकार न हो। गौ-वंश के संरक्षण के साथ बेहतर पोषण की व्यवस्था बने। गौशालाओं के स्वावलंबन, प्रशासनिक, वित्तीय, सामाजिक तथा विधिक विषयों व प्रावधानों पर कार्यशाला में मंथन किया जाकर कार्ययोजना का निर्माण किया जाएगा। गौ-सेवा, गौ-पोषण और संवर्धन के क्षेत्र में ठोस कार्य किए जाएंगे।

गौशाला संचालन पर होगा मंथन

प्रमुख सचिव पशुपालन गुलशन बामरा ने बताया कि कार्यशाला के विभिन्न सत्रों में गौवंश क्षमता अनुसार गौशालाओं का श्रेणीकरण एवं प्रबंधन, आदर्श गौशाला के लिए आवश्यक अधोसंरचना, भूमि, शेड, गोदाम, बिजली, पानी, यंत्र/उपकरण आदि और मानव संसाधन की व्यवस्था के निर्धारण पर मंथन किया जाएगा। गौवंश के उचित रखरखाव संबंधी बेस्ट प्रेक्टिसेस और गौशाला से जुड़े हितधारकों की क्षमता-वर्धन के संबंध में चर्चा की जाएगी। गौशालाओं में आय के विभिन्न स्रोतों से स्वावलंबन प्राप्त करने के लिए शासकीय सहयोग के प्रकार और प्रावधानों पर परामर्श किया जाएगा। साथ ही विभिन्न गौ-उत्पादों के उत्पादन और विपणन पर सुझाव प्राप्त किए जाएंगे। सीएसआर से गौशालाओं के प्रबंधन में सहयोग के विषय में चर्चा की जाएगी।

सामाजिक पहलुओं पर होगी चर्चा

कार्यशाला में गौशालाओं से संबंधित सामाजिक पहलू, पशुपालकों द्वारा गौवंश को स्टॉल फीडिंग के लिए प्रोत्साहित करने के उपाय और घायल, निराश्रित गौवंश को निकटतम गौशालाओं तक पहुचाने हेतु परिवहन की व्यवस्था पर विमर्श किया जाएगा। साथ ही मृत गौवंश का सम्मानपूर्वक निष्पादन भी चर्चा का प्रमुख विषय है। इसके साथ ही गौशालाओं एवं निराश्रित गौवंश से संबंधित विधिक पहलू और गौवंश संरक्षण के संबंध में उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों/ राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देश पर भी प्रकाश डालकर आवश्यक प्रबंधों पर चर्चा की जाएगी।

पंचायत मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने किय आह्वान

गौ-संरक्षण के लिए समाज की सहभागिता जरूरी

इधर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने कहा कि गौ-संरक्षण के लिए समाज की सहभागिता और आपसी समन्वय अत्यंत आवश्यक है। गौशालाओं के संधारण एवं गौ-माता के संरक्षण में जो कठिनाइयां आती है, उनका सामना हम सभी मिलकर कर सकते हैं। मैं स्वयं दमोह जिले में गौ-अभयारण्य का संचालन कर रहा हूं। सामुदायिक चराई अधिकार, भूसे का परिवहन, राजमार्ग से गौशाला की दूरी आदि समस्याओं के बारे में आज सत्र में जो सुझाव आए हैं उन पर शासन स्तर पर चर्चा कर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। देशी गाय की क्षमता एवं उपयोगिता का संपूर्ण विश्व में गुणगान है, हमें भी जमीनी स्तर पर देशी गाय के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। गौ-सेवा की भावना

को हमें समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचना है। गौशालाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए जो भी प्रशासनिक अवरोध है, उन्हें निश्चित रूप से समाप्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शासन द्वारा गौ-कल्याण तथा गौशालाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे।।

बेहतर प्रबंधन के सुझाव- सत्र में पांच पैनलिस्ट एवं दो विषय विशेषज्ञों ने गौ-संरक्षण, दुग्ध प्रोसेस्ड उत्पादों, गौ-मूत्र एवं गोबर की उपयोगिता तथा अन्य विषयों पर अपने विचार रखे। गौशाला संचालकों ने बेहतर प्रबंधन के लिए कई सुझाव दिए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव सहित पशुपालन विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

मौसम विभाग ने की हीटवेव की भविष्यवाणी

सावधान! पड़ेगी प्रचंड गर्मी, बढ़ेगी लू की मार

भोपाल। जागत गांव हमार

केंद्रीय मौसम विज्ञान विभाग ने इस साल देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान रहने का पूर्वानुमान लगाया है। दावा है कि मार्च से मई के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत, उत्तर-पूर्व भारत, मध्य भारत और प्रायद्वीपीय के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में अधिक अधिकतम तापमान रहेगा। खास बात यह है कि इस दौरान भारत के अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। यानी इस साल प्रचंड गर्मी पड़ने वाली है। लोगों को इससे सामना करने के लिए पहले से ही तैयार रहना होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में प्रचंड गर्मी पड़ने की भविष्यवाणी की है। इन राज्यों में हीटवेव वाले दिनों की संख्या में बढ़ोतरी भी हो सकती है। इसका मतलब यह है कि कई दिनों तक इंसान से लेकर जानवरों तक को लू का सामना करना पड़ेगा। खास बात यह है कि मार्च से मई के दौरान आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्से में पसीना बहाने वाली भयंकर गर्मी पड़ेगी।

हो सकती है अधिक बारिश- पूर्वानुमान में मार्च महीने के दौरान पूरे भारत में सामान्य से अधिक वर्षा की भी भविष्यवाणी की गई है। यानी इस महीने अधिकांश क्षेत्रों में सामान्य से अधिक सामान्य वर्षा हो सकती है। जबकि दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र, पूर्वोत्तर और उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में सामान्य से कम वर्षा होगी। इन क्षेत्रों में मौसम अधिक आर्द्र होने की उम्मीद है। साथ ही कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के कई इलाकों और ओडिशा के कुछ हिस्सों में भी लू के दिन बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में बागवानी फसलों के उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है।

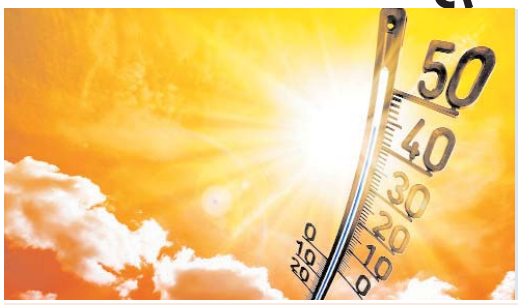

यूपी में भी होगी बारिश

पूर्वानुमान में मार्च महीने में पूर्वी उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि की संभावना भी शामिल है। मौसम विभाग की इन भविष्यवाणियों का उद्देश्य अप्रत्याशित मौसम स्थितियों का सामना करने के लिए तैयारियों को बढ़ाना और आपदा जोखिम को कम करने में सहायता करना है।

तपेगा मध्यप्रदेश मौसम विभाग का कहना है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में मार्च के शुरुआती दिनों गंभीर बारिश की स्थिति बन रही है। खास बात यह है कि बारिश के साथ बिजली और तेज हवा के झोंकों की भी चेतावनी भी जारी की गई है। इसी तरह पश्चिमी हिमालय क्षेत्र भी विशेष रूप से मार्च में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा और बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया है।

आत्मनिर्भर हो रहे किसान, फसल की लागत में आई कमी

सीहोर में नई तकनीक से प्याज का बंपर उत्पादन

भोपाल। जागत गांव हमार

प्याज की खेती करने वाले किसानों को इन दिनों मौसम की मार का सामना करना पड़ रहा है। पर मध्यप्रदेश के सीहोर के किसानों ने प्याज की खेती में अधिक फायदा होने वाली नई तकनीक सीख ली है। इससे उन्हें फायदा हो रहा है। इसके अलावा अब किसानों को मौसम संबंधी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ रहा है। नई तकनीक को अपनाने बाद प्याज की खेती सीहोर के किसानों के लिए फायदे का धंधा बन गई है। जिले के कई किसान नई तकनीक से प्याज की खेती कर लाभ कमा रहे है। इसमें लागत कम और मुनाफा ज्यादा होता है। इसमें अधिक मुनाफे के साथ मजदूरों की भी ज्यादा जरूरत नही पड़ती है। जिले के कई किसान नई तकनीक से प्याज की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। मौसम में परिवर्तन और कम बारिश से जहां फसलों को नुकसान होता है तो वहीं नई तकनीक से प्याज की खेती में कम लागत के साथ ही कम पानी में अच्छी पैदावार होती है।

किसानों का बढ़ रहा रुझान

किसानों का कहना है कि इसमें लागत कम और मुनाफा ज्यादा होता है साथ ही मजदूरों की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। कम पानी में अच्छी पैदावार हो जाती है। जिले के ग्राम रफीगंज के किसान ने बताया कि 5 एकड़ में वह प्याज की खेती नई तकनीक से कर रहे हैं। बीते 2 साल से इसका प्रयोग किया जा रहा है जिसमें प्याज का अच्छा उत्पादन हो रहा है। हमारी नई तकनीक को देखते हुए गांव के अधिकतर किसानों ने इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया है।

कम पानी वाली जमीन में प्याज की खेती

ग्राम रफीगंज के किसान राजेंद्र परमार ने बताया कि पांच एकड़ में वह प्याज खेती करते हैं। पिछले दो सालों से वो नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए प्याज की खेती कर रहे हैं। इसके अच्छे परिणाम मिल रहे है। हमारे गांव में खेती के लिए पर्याप्त पानी नहीं है। कम पानी में भी नई तकनीक से प्याज की खेती में अच्छा उत्पादन होता है। आज के समय मजदूर नहीं मिलते है। नई तकनीक से प्याज की खेती में मजदूर की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है।

ऐसे करते प्याज की खेती

नई तकनीक से प्याज की खेती करने के लिए सबसे पहले खेत में बक्खर चला कर पलेवा करते हैं। इसके बाद खेत को एक महीने तक धूप में छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फिर बक्खर और रोटावेटर चला कर खेल में ढाल बनाई जाती है। इसके बाद इसमें प्याज के बीज को डीएपी के साथ डाला जाता है। इस तकनीक से खेती करने के लिए खेत में समय समय पर पानी के साथ साथ डीएपी का छिड़काव भी करना चाहिए। किसानों के मुताबिक इस तकनीक से खेती करने पर एक एकड़ जमीन लगभग 170-180 क्विंटल प्याज की पैदावार होती है।

छह हजार हेक्टेयर में प्याज की खेती

इस साल सीहोर में 6 हजार हेक्टेयर में प्याज की खेती की गई है। वहीं जिले के कई किसानों ऐसे किसान हैं जिन्होंने इस बार प्याज की खेती करने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया है। साल 2023 - 24 में काफी संख्या में किसानों ने प्याज की खेती की थी। अब इस बार 2024 - 25 में भी काफी संख्या में किसानों वे प्याज की खेती की है। इस बार रकबा 6 हजार हेक्टेयर है।

कृषि मेले का मंत्री कंषाना ने किया शुभारंभ, कहा

जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर किसानों को बढ़ना होगा आगे

भोपाल। जागत गांव हमार

किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने कहा है कि कृषि मेलों के आयोजन से किसान लाभान्वित होंगे। मेलों में किसानों को खेती-किसानी की अत्याधुनिक तकनीकों से अवगत होने का अवसर भी मिलता है और वे लाभान्वित भी होते हैं। कृषि मंत्री भोपाल के बिट्टन मार्केट में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि उद्यानिकी, डेयरी एवं अभियांत्रिकी मेले का शुभारंभ कर संबोधित कर रहे थे। कंषाना ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसानों को लाभान्वित करने के लिए निरंतर नित नये कार्य किए जा रहे हैं। इस प्रकार के उच्च स्तरीय मेलों के आयोजन से किसानों को अत्याधुनिक तकनीकों से रूबरू होने का अवसर मिलता है। खेती-किसानी की बेहतरी के लिये नवीनतम जानकारियां प्राप्त होती हैं। किसानों को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ दिलाने में मदद भी मिलती है। कृषि मंत्री ने मेले में खेती-किसानी के लिए विकसित और निर्मित किए गए आधुनिक उपकरणों का अवलोकन किया। कृषि मंत्री ने मेले में कहा कि हमें जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ना है। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वे अपने खेतों में नैनो यूरिया का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। नैनो यूरिया के प्रयोग से खाद्य उत्पादों की पौष्टिकता बरकरार रहेगी। इससे धरती की उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी। कृषि मंत्री ने मेले के आयोजन के लिये सभी संबद्ध संस्थानों को शुभकामना देते हुए कहा कि सभी मिलकर अन्नदाता के सशक्तिकरण के लिए कार्य करें। इससे समाज, प्रदेश और देश में समृद्धि आएगी।

पशुओं के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण खनिज

» डॉ. ज्योत्सना शक्र रपुडे
» डॉ. मनोज कुमार अहिरवार
» डॉ. अर्चना जैन
» डॉ. कविता रावत
» डॉ. दीपिका डायना जेस्सी ए
» डॉ. रंजीत आइच,
» डॉ. श्वेता राजोरिया,
» डॉ. आम्रपाली भिमटें
» डॉ. गायत्री देवांगन
पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, महू, मप्र

खनिज सभी पशुओ के सर्वोत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। विभिन्न प्रजातियों की अलग-अलग ज़रूरतें होती हैं, लेकिन स्वस्थ शरीर के कामकाज को बनाए रखने के लिए उन सभी को प्रत्येक खनिज की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। खनिज की कमी रोग का कारण बन सकती है, और खनिज की अधिकता रोग का कारण बन सकती है। इसलिए, सही अनुपात में सही मात्रा प्राप्त करना इष्टतम स्वास्थ्य की कुंजी है। अधिकांश प्राकृतिक आहार इन खनिजों को सही संतुलन में प्रदान करेंगे, लेकिन

पशुओं की शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभिन्न खनिज, जैसे-कैल्शियम, फास्फोरस, मैगनीशियम, सोडियम, पोटैशियम, क्लोरीन, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, सल्फर, जिंक, आहार में आयोडीन, फ्लोरीन, मोलिब्डेनम, सेलीनियम, क्रोमियम, सिलिका, निकिल आदि होने चाहिए। कुछ खनिज आहार में प्राकृतिक रूप से विद्यमान होने के कारण, आवश्यकता न होने पर भी शरीर में पहुंच जाते हैं।

अधिकांश मिट्टी में विशेष रूप से सुपरफॉस्फेट की कमी है, और कीटनाशकों और शाकनाशियों के व्यापक उपयोग के कारण मिट्टी का और अधिक क्षरण हुआ है। खनिज की कमी के लक्षण खुरदरी, पपड़ीदार, परतदार त्वचा, गंदगी खाना, खराब विकास, लगातार बीमारी, बाड़ पर चबाना, छाल का नुकसान, अस्वस्थ त्वचा, दांतों की सड़न और बहुत कुछ के रूप में प्रकट हो सकते हैं। **खनिजों का चयापचय:** शरीर में बहुत से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जो जीवन के लिए अत्यन्त आवश्यक होते हैं। कुछ खनिज शरीर के संरचनात्मक घटक होते हैं और अन्य आवश्यक खनिज चयापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं। शरीर में विभिन्न खनिजों की मात्रा भिन्न-भिन्न होती है। पशु-शरीर और पौधों में पाए जाने वाले खनिजों की मात्रा में भिन्नता होती है, जैसे अशिम्बी पौधों में कैल्शियम की मात्रा, पशु-शरीर की अपेक्षा कम होती है। **बोरोन:** कैल्शियम और मैग्नीशियम अवशोषण के लिए आवश्यक है। इसकी केवल थोड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है, बहुत अधिक मात्रा विषैली होती है। जोड़ों का चरमराना बोरोन की कमी का लक्षण हो सकता है। **कैल्शियम:** हड्डियों, दांतों, मांसपेशियों, तंत्रिका तंत्र, हृदय समारोह और रक्त के थक्के के लिए आवश्यक है। इसे मैग्नीशियम के साथ उचित रूप से संतुलित किया जाना चाहिए। कैल्शियम के प्राकृतिक स्रोतों में डोलोमाइट, हड्डियां, अस्थि भोजन, कैमोमाइल, कच्ची हरी सब्जियां या अन्य हरा चारा, गुड़, बीज, मेवे और साबुत अनाज शामिल हैं। **क्लोरीन:** पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के उत्पादन, प्रोटीन पाचन और खनिज अवशोषण के लिए आवश्यक है। क्लोरीन के प्राकृतिक स्रोतों में समुद्री घास, समुद्री मछली, जई, एवोकैडो, वॉटरक्रेस, शतावरी और अनानास शामिल हैं। **क्रोमियम:** एक सहकारक जो रक्त से ग्लूकोज को हटाने के लिए इंसुलिन के साथ काम करता है। **तांबा:** आयरन के अवशोषण, प्रोटीन चयापचय, हड्डियों, तंत्रिकाओं, मस्तिष्क, संयोजी ऊतक और त्वचा के लिए आवश्यक है। कोट का खराब रंग तांबे की कमी का संकेत हो सकता है। गहरे रंग के जानवरों को हल्के रंग के जानवरों की

तुलना में अधिक तांबे की आवश्यकता होती है। आंतरिक परजीवियों से बचाता है। **आयोडीन:** यह स्वस्थ थायरॉइड फ़ंक्शन और त्वचा के लिए आवश्यक है। अधिकता कमी के समान लक्षणों का कारण बनती है। ल्यूसर्न, तिपतिया घास या सोयाबीन के अत्यधिक सेवन से आयोडीन की कमी हो सकती है। आयोडीन के प्राकृतिक स्रोतों में समुद्री मछली, समुद्री शैवाल, समुद्री घास, मछली के जिगर का तेल, अंडे की जर्दी, अनानास, नाशपाती, जलकुंभी शामिल हैं। **आयरन:** यह रक्त का ऑक्सीजन वाहक है। आयरन के अवशोषण के लिए पर्याप्त तांबा, फोलिक एसिड, विटामिन ई और विटामिन सी आवश्यक हैं। आयरन के प्राकृतिक स्रोतों में समुद्री शैवाल, चोकर, जई, जौ, सिंहपर्णी, अजमोद, अंग मांस, स्पिरुलिना, लाल मांस, मछली, अंडे की जर्दी, साबुत अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियाँ शामिल हैं। **मैग्नीशियम:** आधुनिक खेती के तरीकों के कारण कृत्रिम उर्वरकों के उपयोग और फ्लोराइड युक्त पानी पीने से अक्सर इस खनिज की कमी हो जाती है। यह ऊर्जा उत्पादन, तंत्रिका तंत्र, प्रोटीन संश्लेषण, मांसपेशियों की टोन, हृदय क्रिया, हड्डियों और कई अन्य शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक है। **फॉस्फोरस:** हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ संतुलन, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र, कार्बोहाइड्रेट चयापचय और रक्त में एसिड/क्षारीय संतुलन के लिए आवश्यक है। प्राकृतिक स्रोतों में जई, चोकर, काले सूरजमुखी के बीज, गेहूं के बीज, समुद्री शैवाल, कच्चा मांस, मछली, अंडे, साबुत अनाज, मेवे, बीज शामिल हैं। **पोटैशियम:** यह रासायनिक उर्वरकों और मिट्टी में अतिरिक्त लवणता के कारण नष्ट हो जाता है। रक्त में अम्ल/क्षारीय संतुलन बनाए रखता है, हृदय क्रिया, हार्मोन उत्पादन, मांसपेशियों में संकुचन, गुर्दे के कार्य और तंत्रिका तंत्र में सहायता करता है। प्राकृतिक स्रोतों में एप्पल साइडर सिरका, समुद्री शैवाल, केला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं के बीज, काले सूरजमुखी के बीज, अजमोद, नट्स, साबुत अनाज, कच्चा दूध शामिल हैं। **सेलेनियम:** स्वस्थ विकास, मांसपेशियों और प्रजनन क्षमता के लिए आवश्यक। यह एक एंटीऑक्सीडेंट भी है जो लीवर के पुनर्जनन में मदद करता है, उम्र बढ़ने को धीमा करता है और पारा विषाक्तता से बचाता है। यह खाना पकाने, खाद्य प्रसंस्करण और रासायनिक उर्वरकों से नष्ट हो जाता है। **सोडियम:** अधिकांश व्यावसायिक खाद्य पदार्थों में नमक होता है, अतिरिक्त नमक पोटेशियम के स्तर को कम कर सकता है। पोटेशियम और क्लोराइड का सही संतुलन इलेक्ट्रोलाइट संतुलन, शरीर के तरल पदार्थ के नियमन, पेट में एसिड और रक्त में पोषक तत्वों के परिवहन के लिए आवश्यक है। **सल्फर:** यह खनिज त्वचा, बाल और नाखूनों के लिए आवश्यक है। यह एक अच्छा रक्त शोधक और एंटीसेप्टिक भी है। सल्फर की कमी वाले जानवर अक्सर जूँ, पिस्सू और अन्य बाहरी परजीवियों से संक्रमित हो जाते हैं। जिंक - पशुओं में स्वस्थ प्रजनन क्रिया के लिए आवश्यक है।

किसानों का मित्र केंचुआ और किसानों का हमसफर केंचुआ खाद

» डा. घनश्याम बामनिया
» डॉ. धनेश कुमार रैदास
» डॉ. शेखर गोतम दोहरे
सहायक प्राध्यापक, पादप प्रजनन एवं अनुवांशिकी, विभाग, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर सीहोर, मप्र
सहायक प्राध्यापक, पादप कार्यकी विभाग, आरएके कृषि महाविद्यालय, सीहोर, मप्र
सहायक प्राध्यापक, फूडटेक्नोलॉजी, विभाग, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, सीहोर, मप्र

केंचुआ कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत कहा जाता है। यह सेन्द्रिय पदार्थ ऑर्गनिक पदार्थ, ह्यूमस व मिट्टी को एकसार करके जमीन के अन्दर अन्य परतों में फैलाता है। इससे जमीन पोली होती है व हवा का आवागमन बढ़ जाता है, तथा जलधारण की क्षमता भी बढ़ जाती है। केंचुए के पेट में जो रासायनिक क्रिया व सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रिया होती है, उससे भूमि में पाये जाने वाले नत्रजन, स्फुर फॉस्फोरस, पोटाश, कैलशियम व अन्य सूक्ष्म तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है। ऐसा पाया गया है कि मिट्टी में नत्रजन 7 गुना, फास्फोरस 11 गुना और पोटाश 14 गुना बढ़ता है। केंचुए अकेले जमीन को

केंचुए सेन्द्रिय पदार्थ, एवं मिट्टी खाने वाले जीव हैं, जो सेप्रोफेगस वर्ग में आते हैं। इसमें दो प्रकार के केंचुए होते हैं।

1. डेट्रीटीव्होरस: डेट्रीटीव्होरस जमीन के ऊपरी सतह पर पाये जाते हैं। ये लाल चाकलेटी रंग, चपटी पूँछ के होते हैं इनका मुख्य उपयोग खाद बनाने में होता है। ये ह्यूमस फारमर केंचुए कहे जाते हैं।

2. जीओफेगस: जीओ फेगस केंचुए जमीन के अन्दर पाये जाते हैं। ये रंगहीन सुस्त रहते हैं। ये ह्यूमस एवं मिट्टी का मिश्रण बनाकर जमीन पोली करते हैं।

केंचुआ खाद तैयार करने की विधि: जिस कचरे से खाद तैयार की जाना है उसमे से कांच, पत्थर, धातु के टुकड़े अलग करना आवश्यक है। केंचुआ को आधा अपघटित सेन्द्रित पदार्थ खाने को दिया जाता है। भूमि के ऊपर नर्सरी बेड तैयार करें, बेड को लकड़ी से हल्के से पीटकर पक्का व समतल बना लें। इस तह पर 6.7 सेमी 2.3 इंच, मोटी बालू रेत या बजरी की तह बिछायें। बालू रेत की इस तह पर 6 इंच मोटी दोमट मिट्टी की तह बिछायें। दोमट मिट्टी न मिलने पर काली मिट्टी में रॉक पाऊडर पत्थर की खदान का बारीक चूरा मिलाकर बिछायें। इस पर आसानी से

अपघटित हो सकने वाले सेन्द्रिय पदार्थ की नारीयल की बूछ, गन्ने के पत्ते, ज्वार के डंठल एवं अन्य। दोइंच मोटी सतह बनाई जावे। इसके ऊपर 2.3 इंच पकी हुई गोबर खाद डाली जावे। केचुओं को डालने के उपरान्त इसके ऊपर गोबर, पत्ती आदि की 6 से 8 इंच की सतह बनाई जावे। अब इसे मोटी टाट् पट्टी से ढांक दिया जावे। झारे से टाट पट्टी पर आवश्यकतानुसार प्रतिदिन पानी छिड़कते रहे, ताकि 45 से 50 प्रतिशत नमी बनी रहे। नर्सरी बेड में गोबर की खाद कड़क हो गयी हो या ढेले बन गये हो तो इसे हाथ से तोड़ते रहना चाहिए, सप्ताह में एक बार नर्सरी बेड का कचरा ऊपर नीचे करना चाहिये। 30 दिन बाद छोटे छोटे केंचुए दिखना शुरू हो जायेंगे। 31 वें दिन इस बेड पर कूड़े-कचरे की 2 इंच मोटी तह बिछायें और उसे नम करें। इसके बाद हर सप्ताह दो बार कूड़े-कचरे की तह पर तह बिछाएं। बॉयोमास की तह पर पानी छिड़क कर नम करते रहें। 3-4 तह बिछाने के 2-3 दिन बाद उसे हल्के से ऊपर नीचे कर देवें और नमी बनाए रखें। 42 दिन बाद पानी छिड़कना बंद कर दें। इस पद्धति से डेढ़ माह में खाद तैयार हो जाता है। खाद हाथ से अलग करे। गैंती, कुदाली, खुरपी आदि का प्रयोग न करें। केंचुए पर्याप्त बढ़ गए होंगे। नर्सरी को तेज धूप और वर्षा से बचाने के लिये घास.फूस का शेड बनाना आवश्यक है।

केंचुआ और केंचुआ खाद के उपयोग: मिट्टी की दृष्टि से

केंचुए से भूमि की गुणवत्ता सुधरती है। जलधारण क्षमता बढ़ती है। भूमि का उपयुक्त तापक्रम बनाये रखने में सहायक।

कृषकों की दृष्टि से: रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने के साथ काश्त लागत में कमी आती हैं।

पर्यावरण की दृष्टि से: भूमि के जलस्तर में वृद्धि होती है। मिट्टी खाद्य पदार्थ और जमीन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में कमी आती है। बीमारियों में कमी होती है।

अन्य उपयोग: केंचुए से प्राप्त कीमती अमीनों ऐसिड्स एवं एनजाइमस्ए से दवाएं तैयार की जाती हैं। पक्षी, पालतू जानवर, मुर्गियां तथा मछलियों के लिये केचुँए का उपयोग खाद्य सामग्री के रूप में किया जाता है। आयुर्वेदिक औषधियां तैयार करने में इसका उपयोग होता है। केंचुए के सूखे पाउडर में 60 से 65 प्रतिशत प्रोटीन होता है, जिसका उपयोग खाने में किया जाता है।

केंचुआ खाद का महत्व: यह भूमि की उर्वरकता, वातायनता को तो बढ़ाता है, साथ ही भूमि की जल सोखने की क्षमता में भी वृद्धि करता है। वर्मी कम्पोस्ट वाली भूमि में खरपतवार कम उगते हैं तथा पौधों में रोग कम लगते हैं। पौधों तथा भूमि के बीच आयनों के आदान प्रदान में वृद्धि होती हैं। वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग करने वाले खेतों में अलग अलग फसलों के उत्पादन में 25.300: तक की वृद्धि हो सकती हैं। मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती हैं। केंचुओं के मल में पेरीट्रापिक झिल्ली होती हैं, जो जमीन से धूल कणों को चिपकाकर जमीन का वाष्पीकरण होने से रोकती हैं। केंचुओं के शरीर का 85: भाग पानी से बना होता हैं इसलिए सूखे की स्थिति में भी ये अपने शरीर के पानी के कम होने के बावजूद जीवित रह सकते हैं तथा मरने के बाद भूमि को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। वर्मी कम्पोस्ट मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि करता हैं तथा भूमि में जैविक क्रियाओं को निरंतरता प्रदान करता हैं। इसका प्रयोग करने से भूमि उपजाऊ एवं भुरभुरी बनती हैं। यह खेत में दीमक एवं अन्य हानिकारक कीटों को नष्ट कर देता हैं। इससे कीटनाशक की लागत में कमी आती हैं। इसके उपयोग के बाद 2.3 फसलों तक पोषक तत्वों की उपलब्धता बनी रहती हैं। इसके प्रयोग से फलए सब्जी, अनाज की गुणवत्ता में सुधार आता हैं। बहुत कम समय में तैयार हो जाता हैं। केंचुए मिट्टी को ऊपर लाकर उसे उत्तम प्रकार की बनाते हैं।

केंचुआ खाद के उपयोग में सावधानियां: जमीन में केंचुआ खाद का उपयोग करने के बाद रासायनिक खाद व कीटनाशक दवा का उपयोग न करें।

बकरी का दूध अमृत के समान स्वास्थ्य के लिए वरदान

» डॉ. सौरभ शर्मा, » डॉ. रूचि सिंह, » डॉ. प्रतीक्षा ठाकुर, » डॉ. रश्मि विश्वकर्मा, » डॉ. हरी आर
पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर, मप्र

बकरी गरीब आदमी की गाय के रूप में जानी जाती है। भारत में बकरियों की जनसंख्या 135.173 मिलियन है, और यह कुल दूध उत्पादन का 3.0 प्रतिशत उत्पादन करती है। बकरी के दूध की तुलना आमतौर पर गाय के दूध के साथ की जाती है। उत्पादन में अंतर के अलावा गाय के दूध को पचाना कठिन होता है, क्योंकि इनमें वसा की गोलिकायें बड़ी होती हैं, एवं अधिक लैक्टोज होने के कारण शिशुओं में लैक्टोज असहिष्णुता बढ़ जाती है, जिनके लक्षण उल्टी, दस्त, कोलाइटिस, राइनाइटिस आदि होते हैं। गाय के दूध से होने वाली एलर्जी की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जिसके लिए कैसिइन प्रोटीन के उच्च स्तर को जिम्मेदार माना गया है। इसके अलावा गाय के दूध को यांत्रिक रूप से समर्पित करने की आवश्यकता होती है, जिससे खून में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है, जिससे रक्तनली में कोलेस्ट्रोल जमा होने लगता है। इन समस्याओं के कारण लोग बकरी का दूध पसंद करने लगे हैं।

बकरी और गाय के दूध की रासायनिक संरचनाओं में अंतर

विवरण	बकरी का दूध (:)	गाय का दूध (:)
कुल ठोस	12.97	12.01
प्रोटीन	3.56	3.29
फैट	4.14	3.34
लैक्टोज	4.45	4.66

बकरी के दूध के चिकित्सीय लाभ निम्नलिखित है

1. दूध में वसा की गोलिकाएं 1 से 10 माईक्रोन तक होती है, लेकिन 5 माईक्रोन से कम की गोलिकाओं की संख्या गाय के दूध में 60 प्रतिषत है, जबकि बकरी के दूध में 80% है। ये छोटे आकार की गोलिकाएं दूध में बेहतर फैलाव और वसा को सजातीय मिश्रण प्रदान करते हैं, जिससे दूध का पाचन आसान हो जाता है। 2. बकरी का दूध मध्यम श्रृंखला ट्राइग्लिसराइड्स में समृद्ध होता है, जो आंत में अखंड अवशोषित होते हैं एवं तेजी से पाचन में अपना योगदान प्रदान करते हैं। 3. एग्लूटीनिन नामक प्रोटीन बकरी के दूध में अनुपस्थित होता है, जिससे क्रिमिंग दर धीमी हो जाती है बेहतर पाचन हेतु अधिक समय प्राप्त होता है। 4. बकरी के दूध में कैप्रोइक, कैप्रायलिक और कैप्रिक एसिड प्रमुख होते हैं, जो रोगाणुरोधी होते हैं। 5. बकरी के दूध में वसा की गोलिकाएं छोटे आकार की होती हैं, जिससे इन्हें तोड़ने के लिए यांत्रिक तरीकों की आवश्यकता नहीं होती। जबकि गायों के दूध में वसा की बड़ी गोलिकायें यांत्रिक तरीके से टूटती हैं तो यह एक एंजाइम जैंथीन ऑक्सीडेज को रिलीज करती है, जो आंतों की दीवार से रक्त प्रवाह में प्रवेश करती है। जैंथीन के प्रभाव से बचने हेतु रक्तनली कोलेस्ट्रोल स्त्रावित करता है, जिससे रक्त में कोलेस्ट्रोल बढ़ जाता है।

जारी...

ऑनलाइन फसल बिक्री और भुगतान का तेज लाभ मिलेगा

किसानों की आय में उल्लेखनीय सुधार लाने की दिशा में यह बड़ा कदम

पांच हजार किसान उत्पादक संगठन सरकारी ई-कॉमर्स ओएनडीसी से जुड़े

भोपाल। जागत गांव हमार

किसानों की फसल को सही दाम पर बिक्री के लिए केंद्र सरकार के ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ओएनडीसी से पांच हजार किसान उत्पादक संगठन को जोड़ा गया है। जबकि, बाकी 3000 एफपीओ को जल्द ही ओएनडीसी से जोड़ने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ई-कॉमर्स से जुड़ने से उपज की ऑनलाइन बिक्री और भुगतान का तेज लाभ मिलेगा। देशभर में रजिस्टर्ड कुल 8000 किसान उत्पादक संगठन हैं, जो किसानों की फसलों की बिक्री के साथ वित्तीय मदद कर रहे हैं। कृषि मंत्रालय के अनुसार किसानों की फसलों को सही दाम देने और तुरंत भुगतान के लिए सरकार ने साल 2020 में 6,865 करोड़ रुपए के साथ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पोर्टल को शुरू किया था। सरकार ने 10,000 एफपीओ को रजिस्टर करने का लक्ष्य रखा था, जिसके मुकाबले लगभग 8,000 एफपीओ को रजिस्टर किया गया है। इनमें से लगभग 5,000 एफपीओ को देशभर के उपभोक्ताओं को ऑनलाइन उपज बेचने के लिए ओएनडीसी पोर्टल से जोड़ दिया गया है।

3000 एफपीओ को जल्द जोड़ने की तैयारी

कृषि मंत्रालय ने कहा कि लगभग 5,000 को ओएनडीसी पोर्टल पर रजिस्टर किया गया है। इसमें कहा गया है कि देश के किसी भी हिस्से में अपने खरीदारों तक पहुंचने के लिए ओएनडीसी पर एफपीओ को शामिल करना उत्पादकों को बेहतर बाजार पहुंच प्रदान करने के केंद्र सरकार के उद्देश्य का हिस्सा है। इस कदम से एफपीओ को डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन भुगतान, बिजनेस-टू-बिजनेस और बिजनेस-टू-कंज्यूमर लेनदेन तक सीधी पहुंच के साथ सशक्त बनाना है। जबकि, बाकी 3000 एफपीओ को जल्द ही ओएनडीसी से जोड़ने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

अर्थव्यवस्था में सुधार कर रहे

कृषि मंत्रालय के अनुसार एफपीओ का गठन कृषि को आत्मानिर्भर बनने में मदद करने के लिए बड़ा कदम है। यह पहल एफपीओ के सदस्यों के लिए लागत प्रभावी उत्पादन और उत्पादकता और ज्यादा शुद्ध कमाई को बढ़ाती है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी सुधार होता है और ग्रामीण युवाओं के लिए गांवों में ही रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। कहा गया है कि किसानों की आय में उल्लेखनीय सुधार लाने की दिशा में यह बड़ा कदम है।

एफपीओ को सरकार देती है 18 लाख

किसान उत्पादक संगठनों किसानों को बेहतर क्वालिटी वाली वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बेहतर तकनीक, लोन, बेहतर इनपुट और अधिक बाजारों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करते हैं। सरकार हर एफपीओ को 3 साल के लिए 18 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दे रही है। अब तक 10.2 लाख से अधिक किसानों को कवर करते हुए 246 करोड़ की गारंटी कवरेज के लायक 1,101 एफपीओ को क्रेडिट गारंटी जारी की गई है। मंत्रालय ने कहा कि 145.1 करोड़ की मैचिंग इक्विटी अनुदान सीधे पात्र 3,187 एफपीओ के बैंक खाते में भेजी गई है।

मसूर दाल की खरीद के लिए पोर्टल लॉन्च करेगा केंद्र

सरकार ने सबसे पहले अरहर दाल के लिए पहल की थी

मसूर दाल की खरीद पर मिलेगी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी

भोपाल। जागत गांव हमार

दलहन की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार मसूर दाल की खरीद के लिए एक पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने वाले किसानों को उनकी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी दी जाएगी। खास बात यह है कि सरकार ने सबसे पहले अरहर दाल के लिए इस तरह की पहल शुरू की थी। अब वह इसके क्षेत्र में विस्तार ला रही है, जिसके तहत मसूर और अन्य दालों को शामिल करने की तैयारी चल रही है। ताकि किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिल सके। ऐसे में किसान अधिक से अधिक रकबे में दलहन की खेती करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक अधिकारी ने कहा कि हम दलहन कटाई के मौसम से पहले मसूर उत्पादक किसानों का पंजीकरण शुरू करने वाले हैं, ताकि खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। उन्होंने कहा कि किसानों के खातों में सीधा भुगतान किया जाएगा। इससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। अधिकारी ने कहा कि समय पर भुगतान होने से किसानों की दलहन की खेती में रुचि बढ़ेगी और वे अधिक रकबे में इसकी खेती करेंगे। हालांकि, ऐसे दाल की बढ़ती कीमत को नियंत्रित करने के लिए सरका भी पुरी कोशिश कर रही है। वह भारत ब्रांड के तहत खुदरा मार्केट में दाल बेच रही है। इससे आम जनता को काफी राहत मिली है।

भारत बनेगा सबसे बड़ा मसूर उत्पादक देश

भारत दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता हैं, लेकिन घरेलू खपत के लिए यह आयात पर निर्भर हैं। यह कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से मसूर दाल का आयात करता है। दालों के अधिक घरेलू उत्पादन से देश को इनका आयात कम करने में मदद मिलेगी। जबकि जनवरी में खाद्य मुद्रास्फीति दिसंबर के 9.53 प्रतिशत से कम होकर 8.3 प्रतिशत हो गई, लेकिन साल भर पहले की अवधि की तुलना में यह ऊंची बनी हुई है, जब यह 6 प्रतिशत थी। दालों में महंगाई दर 19.54 फीसदी रहना एक प्रमुख कारक रहा है। सरकार को उम्मीद है कि फसल वर्ष 2023-24 में भारत मसूर का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बन जाएगा, क्योंकि अधिक क्षेत्रफल के कारण इस रबी सीजन के दौरान उत्पादन 1.6 मिलियन टन के उच्चतम स्तर पर पहुंचने का अनुमान है।

अरहर की एमएसपी पर होगी खरीद

पिछले महीने केंद्र सरकार अरहर दाल उत्पादकों को सही दाम देने के लिए एमएसपी दर पर खरीद करने की घोषणा की थी। इस बार रबी फसलों की सरकारी खरीद प्रक्रिया करीब 25 से 30 दिन पहले शुरू हो रही है। केंद्र ने एफसीआई के अलावा सहकारी समितियों को किसानों से उनकी फसल खरीदने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में तूर दाल की उपज खरीद करने की जिम्मेदारी सहकारी समिति नेफेड को सौंपी गई है। नेफेड ने किसानों से अपनी उपज एमएसपी पर बेचने के लिए ई-समृद्धि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने को कहा है। 2023-24 के लिए तुअर दाल पर एमएसपी रेट 300 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है।

बैतूल के आदिवासी किसान राजकुमार सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार से सम्मानित

बैतूल। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केन्द्र, बैतूल के संपर्क कृषक राजकुमार सिरोरिया द्वारा श्री अन्न के उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए सोसायटी ऑफ कृषि विज्ञान, अमृतसर, पंजाब एवं फोरम ऑफ केव्हीके एंड एआईसीआरपी जोरहट, असम के संयुक्त तत्वाधान में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर में आयोजित चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन में राजकुमार सिरोरिया को सम्मानित किया गया। आदिवासी जिला बैतूल में श्री अन्न (कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, सांवा, कंगनी, रागी आदि) के उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं, परम्परागत रूप से इन फसलों का बैतूल में बहुलता से उत्पादन होता रहा है। इनके प्रसंस्करण एवं समुचित विपणन की प्रभावी व्यवस्था नहीं होने के कारण ये फसलें कृषकों के लिए ज्यादा लाभदायक नहीं हो रही थी जिससे इनका क्षेत्रफल एवं उत्पादन लगातार कम हो रहा था। सिरोरिया द्वारा किए गए कार्यों से कृषकों विशेष रूप से छोटे आदिवासी कृषकों को जो कि श्री अन्न के उत्पादक है, आर्थिक लाभ मिलेगा। ये फसलें कृषि क्षेत्र में जैव विविधता के लिए आवश्यक है। अगर इन फसलों को प्रोत्साहन मिलें तो जिले की अन्य फसलों की उत्पादकता एवं उत्पादन लागत में भी कमी आ जाएगी। इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखकर कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों द्वारा इन फसलों को बढ़ावा देने के लिए युवा कृषकों को लगातार प्रोत्साहित किया गया। परिणामस्वरूप राजकुमार सिरोरिया द्वारा इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया गया जिसको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है।

केवीके द्वारा गोहद के टुंडीला गांव में प्राकृतिक कृषि पर प्रशिक्षण आयोजित

एक देशी गाय से 30 एकड़ में प्राकृतिक खेती संभव

लहार (भिंड)। जागत गांव हमार

भारत सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों में जागरूकता लाने के लिए प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम चला रही है। इसी क्रम में कृषि विज्ञान केंद्र लहार द्वारा गोहद क्षेत्र के टुंडीला गांव में एक दो दिवसीय प्राकृतिक कृषि पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जिसमें केंद्र के वैज्ञानिकों ने किसानों को प्राकृतिक कृषि के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई।

प्रशिक्षण को संबोधित करते हुए केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. एसपी सिंह ने बताया कि प्राकृतिक कृषि में देशी गाय का बहुत अधिक महत्व होता है। बिना देसी गाय के गो मूत्र-गोबर के प्राकृतिक कृषिकरना संभव नहीं हैं। उन्होंने बताया कि आज पूरे विश्व में तीन तरह की कृषि पद्धतियां प्रचलन में हैं। जिसमें रासायनिक कृषि, जैविक कृषि एवं प्राकृतिक कृषि प्रमुख हैं। जैविक कृषि में जहां एक एकड़ भूमि में खेती करने के लिए 30 गाय या 30 पशुओं के गोबर की आवश्यकता होती है। वहीं प्राकृतिक कृषि में मात्र एक देसी गाय के गोबर एवं गोमूत्र से 30 एकड़ में प्राकृतिक कृषि की जा सकती है। देशी गाय के एक ग्राम गोबर में 300 से लेकर 500 करोड़ तक सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। प्राकृतिक कृषि में गोबर एवं गौ मूत्र से जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत के साथ ही नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र,

अग्निअस्त्र आदि तैयार करके जमीन में प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक कृषि में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट एवं अन्य जैविक खाद की कोई आवश्यकता नहीं होती है। गाय के गोबर-गोमूत्र एवं पेड़ पौधों की पत्तियों व अन्य पदार्थों से तैयार उत्पाद ही प्राकृतिक कृषि में प्रयोग किए जाते हैं। खेती में जब लगातार प्राकृतिक कृषि उत्पादों को प्रयोग किया जाता है तो जमीन की उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी होने के साथ ही भूमि की दशा और दिशा में भी सुधार होता है। डॉ. एसपी सिंह ने कहा कि यदि किसान प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ते हैं तो इससे घुमंतू देशी गाय की समस्या का समाधान होने के साथ ही खेती पर आने वाली लागत को काफी हद तक कम किया जा सकता है। साथ ही साथ प्राकृतिक कृषि के माध्यम से कीटनाशकों आदि के दुष्प्रभाव से हो रही स्वास्थ्य हानि को भी पूरी तरह रोका जाना संभव है। इसलिए किसानों को चाहिए कि वह प्राकृतिक कृषि की और आगे बढ़े और इसे अपनायें। उन्होंने विशेष रूप से जोर देकर कहा कि खरीफ मौसम में 70ल से अधिक खाली पड़ी हुई जिले की भूमि पर ज्वार-बाजरा की खेती प्राकृतिक कृषि के माध्यम से बखूबी की जा सकती है। इससे किसानों को लाभ होने के साथ एक अतिरिक्त फसल भी मिल सकेगी।

मौके पर ही प्राकृतिक कृषि के उत्पाद जीवमृत भी बनाकर सिखाया गया

प्रशिक्षण में केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. करणवीर सिंह, वैज्ञानिक डॉ. नरेंद्र भदोरिया एवं कार्यक्रम के प्रभारी डॉ. बीपीएस रघुवंशी द्वारा भी किसानों को प्राकृतिक कृषि के बारे में बताया गया। प्रशिक्षण के दूसरे दिन किसानों को मौके पर ही प्राकृतिक कृषि के उत्पाद जीवमृत भी बनाकर सिखाया गया। गौरतलब है कि पूरे भारतवर्ष में 732 कृषि विज्ञान केंद्र कार्य कर रहे हैं जिसमें से लगभग आधे से अधिक कृषि विज्ञान केंद्रों में भारत सरकार के माध्यम से प्राकृतिक कृषि परियोजना संचालित की जा रही है। जिसके तहत- किसानों को प्राकृतिक कृषिके प्रति जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण-प्रदर्शन आदि कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। भिंड जिले में भी कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक कृषि के प्रति जागरूक किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा अब तक किसानों को दो दिवसीय 6 प्रशिक्षण तथा कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। केंद्र द्वारा जिले के विभिन्न विकास खंडो के गांव में जाकर मौके पर ही किसानों के बीच में यह प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

मौसमी टीकाकरण के बारे में पशु पालकों को बताया गया

पशु स्वास्थ्य शिविर का आयोजन

टीकमगढ़। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ द्वारा संचालित निकरा परियोजना जलवायु समुत्थानुशील कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार के अंतर्गत अंगीकृत ग्राम कोडिया ब्लॉक-जतारा जिला टीकमगढ़, में पशु स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। पशु स्वास्थ्य शिविर के आयोजन का मुख्या उद्देश्य किसानों के बीच उनके पशुओं के रोग, कीट, पोषण एवं रखरखाव के प्रति जागरूकता लाने के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गाय, भैंस एवं बकरी आदि की बीमारियां जैसे खुरपका-मुंहपका, गलघोटू, लंगड़ा बुखार, ब्रुसेलोसिस, रेबीज, एंथ्रेक्स, थाइलेरियोसिस, थनैला एवं कीट जैसे चिचड़, मक्खी, पेट के कीड़े इत्यादि का इलाज, टीकाकरण एवं बचाव के लिए जानकारी दी गई। वर्तमान में बकरियों में चिचड़ कीट की समस्या अधिक देखी गई है, इसके नियंत्रण एवं बचाव हेतु दवाई एवं सुझाव दिए गए । पशुपालक

कृषकों को बताया गया की सावधानियां रखना इलाज कराने से बेहतर होता है अर्थात किसान पशुओं को संतुलित आहार, समय-समय पर टीकाकरण एवं साफ-स्वच्छ पानी के प्रबंधन करते हैं तो अधिकतर बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है संतुलित आहार में खाली, अनाज, अनाज के उत्पाद(जैसे चुनी, दलिया), हरा चारा एवं सूखा चारा पशुओं की उम्र एवं कार्य क्षमता के अनुसार दिया जाता है। संतुलित आहार न मिलने पर पशुओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जैसे- दुधारू पशुओं में दुग्ध उत्पादन क्षमता कम होना एवं बकरियों के पूर्ण विकास ना होना जिससे किसानों की आय प्रभावित होती है। संतुलित आहार की विस्तृत एवं पूर्ण जानकारी के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा विकसित एवं संचालित पशु पोषण एप्लीकेशन मोबाईल में डाउनलोड करने के बारे में शिखाया गया। पशु स्वास्थ्य शिविर में पशुपालन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। शिविर में कृषि विज्ञान केंद्र के डॉ. बीएस किरार प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. आरके प्रजापति, डॉ. यू.एस. धाकड़, डॉ. एसके जाटव, जयपाल छिगारहा एवं पशुपालन विभाग से एवीएफओ डॉ. मनीष प्रजापति सहित 55 कृषक उपस्थित रहे। शिविर में 37 गाय, 43 भैंस एवं 120 बकरियों का इलाज किया गया।

कृषि विज्ञान मेले में वैज्ञानिकों ने दिया उन्नत खेती का प्रशिक्षण

सागर। जागत गांव हमार

जिला कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देशन में किसान कल्याण एवं कृषि विभाग आत्मा परियोजना द्वारा दिनांक 5 एवं 6 मार्च 2024 को कृषि विज्ञान केंद्र सागर में दो दिवसीय कृषि विज्ञान मेला का आयोजन किया गया। उक्त मेले का आयोजन संयुक्त संचालक एवं उपसंचालक बीएल मालवी के मार्गदर्शन में विभाग द्वारा संपादित किया गया।

कृषि विज्ञान मेला में तकनीकी मार्गदर्शन कृषि विज्ञान केंद्र सागर एक एवं दो के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. केएस यादव, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. एके त्रिपाठी के निर्देशन में वैज्ञानिकों द्वारा विविध विषयों ग्रीष्म कालीन गहरी जुताई एवं उसका महत्व जायद फसलों सोयाबीन, मक्का आदि की उन्नत उत्पादन तकनीकी सब्जियों की उन्नत खेती, पोषक तत्व प्रबंधन, मिट्टी परीक्षण, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती मोटे अनाज की खेती एवं मूल्य संवर्धन, ग्रीष्मकाल में पशुधन प्रबंधन आदि विविध विषय पर प्रशिक्षण दिया गया। इन विषयों पर प्रमुख रूप से केंद्र के वैज्ञानिक डॉ, एसके तिवारी, डॉ वैशाली शर्मा, डी.पी. सिंह, मयंक मेहरा, सुखलाल बास्केल आदि द्वारा प्रशिक्षण

प्रदान किया गया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा उत्कृष्ट किस्म की प्रदर्शनी भी लगाई गई। विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी कृषि विभाग के अधिकारी एसपी भारद्वाज, एसके जैन, अरविंद गुप्ता, राजपूत उद्यान विभाग इफको मैनेजर प्रतीक गुप्ता आदि ने जानकारी प्रदान की।

डॉ. संजय जैन को सर्वोत्तम पोस्टर प्रस्तुति पुरस्कार

बैतूल। जागत गांव हमार

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर में सोसायटी ऑफ कृषि विज्ञान, अमृतसर, पंजाब एवं फोरम ऑफ केवीके एंड एआईसीआरपी जोरहट, असम के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न तीन दिवसीय अखिल भारतीय स्तर के आयोजित कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र, बैतूल में पदस्थ डॉ. संजय जैन, कार्यक्रम सहायक को सर्वोत्तम पोस्टर प्रस्तुति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री जैन को यह पुरस्कार टेक्नोलॉजी असेसमेंट फॉर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर फॉर राइस-व्हीट-

ग्रीन ग्राम क्रोपिंग सिस्टम यूजिंग हेप्पी सीडर इन बैतूल डिस्ट्रीक्ट विषय पर शोध पत्र प्रस्तुतिकरण के लिए दिया गया। 1-3 मार्च 2024 तक तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र के पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि डॉ. जेएस मिश्रा, निदेशक राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर, विषिष्ट अतिथि डॉ. एसआरके सिंह, निदेशक अटारी अंचल-9, जबलपुर, कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉ. डीपी शर्मा, संचालक विस्तार सेवाएं, ज.ने.कृ.विवि जबलपुर तथा डॉ. ओम गुप्ता, सेवानिवृत संचालक विस्तार सेवाएं, जनेकृ विवि जबलपुर मौजूद थे। कार्यक्रम में भारतवर्ष के कृषि वैज्ञानिकों, छात्रों एवं कृषकों ने भाग लेकर कृषि विज्ञान एवं अनुसंधान की बारीकियों, कृषि आधुनिकीकरण एवं एआई का कृषि में अनुप्रयोग आदि विषयों पर व्याख्यान, प्रस्तुतिकरण एवं चिंतन किया। कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों डॉ. व्हीके वर्मा, आरडी बारपेटे एवं डॉ. संजीव वर्मा ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए डॉ. संजय जैन को बधाई दी एवं उनके उज्वल भविष्य की कामना की।

सावधान!
क्षमता से 50 फीसदी कम हुआ पानी

देश के बड़े-बड़े बांधों में पानी का स्तर गिरा

भोपाल। जागत गांव हमार

अल नीनो का असर दिखने लगा है। यह असर बांधों में पानी की स्थिति को लेकर है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में 2024 तक अल नीनो का असर रहेगा, जिससे बारिश कम और तापमान में वृद्धि दर्ज की जा सकती है। इससे खेती-बाड़ी से लेकर पेयजल आदि की तमाम परेशानियां सामने आ सकती हैं। बिजली उत्पादन पर संभावित असर भी इसमें शामिल है, लेकिन उससे पहले राष्ट्रीय जल आयोग की एक रिपोर्ट चौंकाने वाली है। रिपोर्ट बताती है कि देश के 60 फीसद बांधों में पानी का स्तर 50 फीसदी से कम है। राष्ट्रीय जल आयोग हर हफ्ते बांधों में पानी के स्तर पर रिपोर्ट जारी करता है। यह रिपोर्ट कहती है कि देश के प्रमुख बांधों में 60 फीसदी ऐसे हैं जिनमें पानी का स्तर जरूरी लेवल से 50 फीसदी तक कम है। इस रिपोर्ट में बांधों में पानी का लाइव स्टोरेज स्टेटस बताया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के 14 राज्यों में बांधों का जलस्तर सामान्य से कम है।

जलाशयों में पानी कम

देश के प्रमुख जलाशयों में 89 ऐसे हैं जिनमें पानी का स्तर 50 परसेंट से कम है। 66 परसेंट बांध ऐसे हैं जिनमें जलस्तर 40 परसेंट से कम है। बड़ी बात ये है कि इन बांधों में अधिकांश देश के दक्षिणी राज्यों में हैं। प्रमुख बांधों में पानी का स्तर 77.3999 बिलियन क्यूबिक मीटर से घटकर 178.74 बीसीएम पर आ गया है। यह 43 परसेंट पानी का स्तर बताता है। इसी अवधि में पिछले साल का रिकॉर्ड देखें तो स्टोरेज 83 परसेंट था जबकि 10 साल पहले पानी का स्तर 94 फीसदी था।

चिंताजनक रिपोर्ट- राष्ट्रीय जल आयोग की रिपोर्ट कहती है कि देश के दक्षिणी और उत्तरी भागों के बांधों में पानी का स्तर चिंता पैदा करने वाला है। इन दोनों हिस्सों में बांधों में जलस्तर क्रमशः 28 और 37 प्रतिशत तक गिर गया है।

आईएमडी की रिपोर्ट

आईएमडी की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के 711 जिलों में 63 परसेंट ऐसे हैं जहां इस साल की शुरुआत से बारिश की घोर कमी है या सूखे जैसे हालात हैं। इसका असर देश के कई हिस्सों में दिखने भी लगा है। दक्षिण भारत के राज्यों में कई फसलों की अप्रैल में कटनी होने वाली है, लेकिन अभी उन फसलों के लिए पानी की घोर कमी देखी जा रही है। इससे पैदावार में गिरावट की आशंका है। पानी की कमी से जायद (गर्मी) की फसल पर भी खराब असर पड़ सकता है। इतना ही नहीं, दक्षिण पश्चिम मानसून इस साल समय पर नहीं आएगा तो खरीफ फसल की बुवाई भी प्रभावित हो सकती है।

ग्रीष्मकालीन फसलों की बोवनी हो गई शुरू

देशभर में धान-दलहन का करबा बढ़ा

भोपाल। जागत गांव हमार

ग्रीष्मकालीन चावल की बुवाई ने जोर पकड़ लिया है। इस साल एक मार्च तक 23.96 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोवनी हो चुकी है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान इसका एरिया सिर्फ 22.06 लाख हेक्टेयर था। यानी इस बार धान का एरिया 1.896 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने ग्रीष्मकालीन फसलों के तहत प्रारंभिक क्षेत्र कवरेज की रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक दलहन का क्षेत्र पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 1.68 लाख हेक्टेयर था जो इस बार बढ़कर 1.77 लाख हेक्टेयर हो गया है। यह एक सुखद संकेत है। श्री अन्न यानी मोटे अनाज का एरिया भी बढ़ गया है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 1.94 लाख हेक्टेयर की तुलना में इस वर्ष इसी अवधि में लगभग 2.13 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवरेज की सूचना दी गई है। तिलहन फसलों का एरिया पिछले साल के बराबर ही है। अब तक देश में 2.78 लाख हेक्टेयर एरिया में ग्रीष्मकालीन तिलहन की बुवाई हो चुकी है। विभिन्न फसलों के यह शुरुआती आंकड़े हैं। इसमें बदलाव होते रहेंगे। मूंग की बुवाई 1.201 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो पिछले साल के मुकाबले 0.103 लाख हेक्टेयर अधिक है। हालांकि पिछले पांच साल की बोवनी का औसत देखें तो यह 14.149 लाख हेक्टेयर था। उस हिसाब से बोवनी कम दिख रही है। उड़द की बुवाई अब तक सिर्फ 0.509 लाख हेक्टेयर में ही हुई है, जो पिछले साल से मामूली कम है।

बाजरा की कितनी हुई बुवाई

ज्वार की बोवनी एक मार्च तक देश में 0.067 लाख हेक्टेयर में हुई है। जबकि पिछले साल की इसी अवधि में बुवाई 0.064 लाख हेक्टेयर में हुई थी। बाजरा की बुवाई 0.336 लाख हेक्टेयर में हुई है जो पिछले साल से कम है। हालांकि अगर पांच साल की बोवनी का औसत देखें तो यह 4.028 लाख हेक्टेयर था। रागी की बुवाई अब तक सिर्फ 0.056 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो पिछले वर्ष से कम है। इसी तरह मक्के की बोवनी 1.669 लाख हेक्टेयर में हुई है जो पिछले साल से थोड़ा अधिक है। हालांकि पांच साल की बोवनी का औसत देखें तो यह 6.723 लाख हेक्टेयर है।

तिल की बुवाई बढ़ी

केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार मूंगफली की बोवनी 1.748 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो पिछले साल से कम है। मूंगफली की पांच साल की बोवनी का औसत 4.999 लाख हेक्टेयर है। सूरजमुखी की बोवनी 0.166 लाख हेक्टेयर में हुई है जो पिछले वर्ष के मुकाबले थोड़ा कम है। तिल की बोवनी एक मार्च तक 0.750 लाख हेक्टेयर में हुई है जो 2023 में इसी अवधि के मुकाबले 0.072 लाख हेक्टेयर ज्यादा है।

कृषि मेले में किसानों को दी समसामयिक खेती की जानकारी

फसलों की लागत कम करने और खेती में जैविक खाद का सुझाव

सागर। जागत गांव हमार

गति दिवस सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, आत्मा योजना अंतर्गत कृषि विज्ञान केन्द्र, सागर में कृषि विभाग द्वारा कृषि विज्ञान मेले के आयोजन में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को समसमायिक जानकारी सहित विविध विषयों जैसे मूंग, उडद की उन्नत खेती, ड्रोन का उपयोग एवं महत्व, समन्वित कीट एवं रोगनाशी का प्रबंधन, फर्टीगेशन मेथड से ड्रिप खेती, फसलों की लागत कम करने के उपाय, खेती में जैविक उर्वरकों का उपयोग, ग्रीष्मकाल में फलदार वृक्ष लगाने के लिए फल-बाग प्रबंधन एवं अजोला, नेपियर घास एवं पशुओं का ग्रीष्मकाल में प्रबंधन सहित मूल्य संवर्धन तकनीकी पर व्याख्यान दिया गया। इस अवसर पर भिंड से माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन सिंह यादव द्वारा 25 लाख से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना एवं 193 करोड लागत के 68 विकास केन्द्रों का भिंड से लोकार्पण किया गया। जिसका कार्यक्रम में सजीव प्रसारण किया गया।

कार्यक्रम का आयोजन जिला पंचायत स्थायी कृषि समिति के अध्यक्ष संतोष पटेल के मुख्य आतिथ्य में एवं कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. केएस यादव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केन्द्र सागर, कृषि विज्ञान केन्द्र बिजौरा, पैरागॉन ईरीगेशन, मान्सेपा मार्केटिंग, कम्पो एक्सपर्ट, नेटाफेम ईरीगेशन इंडिया प्राइवेट लिमि, इफको आदि द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही कृषि विज्ञान केन्द्र, सागर में विभिन्न प्रकार की प्रदर्शन इकाइयों का भी किसानों द्वारा जीवंत अवलोकन किया गया। मुख्य अतिथि संतोष पटेल एवं संयुक्त संचालक बीएल मालवीय द्वारा इस अवसर पर विभिन्न किसानों एवं कृषि विज्ञान केन्द के वैज्ञानिकों को उत्कृष्ट कार्य के लिए एवं उत्कृष्ट प्रदर्शनी लगाने के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केन्द्र बिजौरा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. आशीष त्रिपाठी, कृषि विभाग के सहायक संचालक जितेन्द्र राजपूत, भूपेन्द्र राजपूत, शैलेन्द्र पांडे, सहित वैज्ञानिक डॉ. वैशाली शर्मा, डीपी सिंह, मयंक मेहरा एवं कृषि अधिकारी उपस्थित थे।

–सिंधिया राजवंश में 1916 में हुआ था निर्माण

मप्र का पहला पंचायत भवन होगा संरक्षित

भोपाल। मध्य प्रदेश का पहला पंचायत भवन सिंधिया राजवंश के समय शिवपुरी के ठकुरपुरा में बनाया गया था। इस पंचायत भवन में तत्समय पंचों की बैठकें होती थीं और जन समस्याओं का निराकरण किया जाता था। प्रदेश का पहला पंचायत भवन दशकों से देखरेख के अभाव में जीर्ण-शीर्ण हो गया। अनदेखी के चलते पंचायत भवन की दीवारों में दरारें आ गईं। छत पर पेड़ उग आए और बाउंड्री टूट गई। यहां आसपास काफी गंदगी इकट्ठी हो गई है। इसी क्रम में पारंपरिक एवं प्राकृतिक वास्तुकला पर काम करने वाली 'आगौर स्टूडियो' की टीम पिछले दिनों भोपाल से शिवपुरी आई। उक्त टीम में शामिल लोगों ने भवन की बनावट का पूरा अध्ययन करके इसके मरम्मत के लिए कुछ सुझाव भी भेजे हैं। उन्होंने कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी से मिलकर उन्हें भी इससे अवगत कराया। इसके अलावा टीम ने ठकुरपुरा में समुदाय के साथ बैठक की और इस भवन को बच्चों एवं महिलाओं के लिए एक कम्युनिटी सेंटर बनाने की चर्चा की जिससे यह भवन जीवंत हो सके। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सब मिलकर इसका उपयोग और संरक्षित करें। प्रदेश के पहले पंचायत भवन को संरक्षित करने के संबंध में एक आवेदन और प्रपोजल शिवपुरी कलेक्टर को दिया गया है, जिस पर उन्होंने नगर पालिका सीएमओ सहित जिला पर्यटन संवर्धन परिषद को पत्र लिख कर इसके संरक्षण के संबंध में निर्देश जारी किए हैं।

1916 में बनाया गया था भवन

जनहित के मुद्दों पर काम करने वाली संस्था जेनिथ के अभय जैन के अनुसार जब यह टीम आई तो उन्होंने इस भवन को लेकर काफी कुछ खंगालने का प्रयास किया। इस दौरान यह सामने आया है कि यह भवन वर्ष 1916 में निर्मित करवाया गया था। इस भवन में पंच बैठकर पंचायत करते थे और समुदाय की समस्याओं का निराकरण करते थे। इस बात की पुष्टि ठकुरपुरा में हुई समुदाय की बैठक में कई बुजुर्गों ने भी की है। इसके बाद वर्ष 1966 को फोटो भी सामने आया है जिसमें इस पंचायत भवन में स्कूल का संचालन हो रहा है। इस इमारत पर बकायदा पंचायत भवन अंकित भी है। उनके अनुसार वह इस विषय में और भी दस्तावेज निकलवाने का प्रयास कर रहे हैं। अभय के अनुसार वह इस भवन के संबंध में सोमवार को कलेक्टर से मिले थे और उन्होंने इस भवन के संरक्षण के लिए संबंधित विभागों को पत्र लिखा है।इस इस संबंध में जब इतिहासकार अशोक मोहित से बात की गई तो उनका कहना था कि सिंधिया राजवंश के महाराज माधवराव सिंधिया प्रथम महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक से काफी प्रभावित थे। उस समय की सिंधिया राजवंश की एक किताब भी है, जिसमें 1913 से 1940 तक वर्णन हैं।

प्रदेश में बारिश के साथ गिरे ओले गेहूं-चने, सरसों की फसलें तबाह

» जिलों में सरकार ने शुरू कराया फसल सर्वे को कार्य

» खंडवा और टीकमगढ़ में भी किसानों को हुआ भारी नुकसान

भोपाल। **मध्यप्रदेश में बेमौसम बारिश** और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा और नर्मदापुरम में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हुई, बिजली और ओले भी गिरे। जबलपुर, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नरसिंहपुर, भोपाल समेत 15 जिलों में ओलावृष्टि हो चुकी है। मौसम में हुए बदलाव ने मध्यप्रदेश में फसलों पर संकट खड़ा कर दिया है। भोपाल, सीहोर, नर्मदापुरम, खंडवा, छिंदवाड़ा, टीकमगढ़, बैतूल, निवाड़ी जिलों में ओले गिरे हैं। कुछ जगह बारिश ने खेतों में कटी रखी फसल डूबो दी। भीगने से गेहूं का दाना काला पड़ने की आशंका है। खजुराहो में भी ओलों ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है। बैतूल प्रशासन ने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं। नर्मदापुरम के इटारसी, डोलरिया, पतलई और सिवनीमालवा में ओले गिरे हैं।

खंडवा में 10 गांव ओला प्रभावित

खंडवा में हरसूद और छनेरा तहसील के 10 से ज्यादा गांव ओलों से प्रभावित हुए हैं। हरसूद में रात 11.32 से 11.52 तक ओलावृष्टि हुई। हरसूद तहसील के प्रतापुरा गांव में फसलों को 100 प्रतिशत नुकसान की बात कही जा रही है। बैतूल में शाहपुर, भौंरा, चिचोली में जोरदार बारिश से खेत में खड़ी और काट कर रखी फसलों को नुकसान हुआ है। वहीं भीमपुर में बिजली गिरने से 15 बकरियां, शाहपुर में एक गाय मर गई। मगरडोह के किसान रामू मालवीय, टेकरीपुरा के नंदू यादव के खेतों में लगी चना और सरसों की फसलों को नुकसान हुआ है। चिचोली में जीन, अटारी, बोरगांव, टहली, कुम्हली, दनोरा में बारिश के कारण खेतों में रखी फसल बारिश के पानी में डूब गई। इससे गेहूं का दाना काला हो जाएगा। भौंरा के ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी एसएल मर्सकोले ने बताया कि एक से दो किमी में ओले गिरे हैं। हवा व बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा है। अब राजस्व अमला सर्वे कर रहा है।

केला, गेहूं, चना, तरबूज की फसल खराब

बुरहानपुर में बेमौसम बारिश के कारण केला, गेहूं, चना और तरबूज फसल को नुकसान पहुंचा है। जिन क्षेत्रों में ओले गिरे हैं, वहां केला और तरबूज भी प्रभावित हुआ है। इसके अलावा अंबाड़ा, सारोला, निंबोला में भी गेहूं फसल को नुकसान हुआ है। जिले के भावसा मोरखेड़ा, बड़सिंग, मोहद, बंभाड़ा में गेहूं, चना, तरबूज की फसल को नुकसान पहुंचा है। भावसा के किसान फूलसिंग बारेला ने बताया खेत में फसल आड़ी हो गई।

सर्वे करने के लिए कलेक्टरों को आदेश

प्रदेश में हुई ओलावृष्टि और अतिवृष्टि को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नुकसान हुए फसलों का सर्वे करने के लिए सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। कोई भी किसान जो प्रभावित हुआ है, उसका सर्वे गंभीरता के साथ किया जाए। उन्होंने कहा कि फसलों का सर्वे कराकर किसानों को उचित राहत राशि उपलब्ध कराई जाए। सर्वे की मॉनिटरिंग करने के लिए सभी मंत्रीगण, विधायकगण और सांसदों को भी कहा गया है।

एआई किसानों को बताएगा कौन सी फसल बोने से ज्यादा लाभ

भोपाल। केंद्र सरकार देश में कृषि प्रणाली को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से जलवायु अनुकूल बनाने की तैयारी कर रही है। इससे किसानों को यह जानकारी पहले ही मिल जाएगी कि उनके क्षेत्र में इस बार मौसम कैसा रहेगा। इसके लिए सरकार एक एआई संचालित कृषि प्रबंधन सॉफ्टवेयर बना रही है। यह सॉफ्टवेयर किसानों को यह बताने में सक्षम होगा कि उनके क्षेत्र में सूखा, बाढ़, लू, शीतलहर, असामान्य बारिश, शुष्क मौसम, ठंड, चक्रवात और ओलावृष्टि की क्या स्थिति रहेगी। ऐसे वातावरण में उन्हें कौन सी फसल बोने से फायदा होगा। इस कार्य में मौसम विभाग के वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक को शामिल किया गया है। जिन्हें सॉफ्टवेयर में शामिल किया जाएगा। वहीं सॉफ्टवेयर बनने के बाद सरकार इस योजना को पूरे देश में लागू करेगी। सॉफ्टवेयर किसी भी क्षेत्र के पिछले 100 साल के मौसम पैटर्न का अध्ययन तुरंत करने में सक्षम होगा। यह 24 घंटे ऑनलाइन मोड में देश की सभी भाषाओं में जानकारी देगा। जब भी किसान अपने क्षेत्र की जानकारी सॉफ्टवेयर में डालेगा तो उसे सलाह मिलेगी। सॉफ्टवेयर एप बेस्ड होगा या वेबसाइट पर, इस संदर्भ में निर्णय नहीं हुआ है। हालांकि इसको सरल बनाया जाएगा ताकि हर क्षेत्र का किसान इससे जानकारी हासिल कर अपनी फसल को लेकर कार्य कर सके। वहीं मौसम के अनुसार अपनी फसल लगा सकें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पर्यावरण मंत्रालय के साथ मिलकर राज्यों में 650 जिलों में खेती पर वातावरण और मौसम के पड़ने वाले प्रभाव का दो दशकों के डेटा का अध्ययन किया। इसमें 310 जिले ऐसे मिले, जहां मौसम की मार से हर साल किसानों को भारी नुकसान होता है।

» सॉफ्टवेयर 100 साल के मौसम का अध्ययन करने में होगा सक्षम

» शोध में 109 जिले अत्यधिक और 201 जिले जोखिम वाले मिले

श्योपुर में उप कृषि उपज मंडियों के हाल बेहाल, कहीं खरीद नहीं तो कहीं सुविधाओं का अकाल

श्योपुर। जागत गांव हमार

भले ही रबी फसलों की कटाई चल रही है और कई जगह सरसों सहित अन्य फसल बिकने के लिए मंडी में पहुंचना शुरू हो गई है। लेकिन जिले के ग्रामीण क्षेत्र में संचालित उप कृषि उपज मंडियों के हाल बेहाल नजर आ रहे हैं। क्योंकि इन उप मंडियों में सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं हैं। स्थिति यह बन रही है कि कहीं उप मंडियों में खरीद नहीं हो रही है तो कहीं सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। जिस कारण किसान और व्यापारी दोनो परेशान बने हुए है और मंडी प्रशासन के जिम्मेदार अफसर इस दिशा में गंभीरता नहीं दिखा रहे है। दरअसल, श्योपुर जिला मुख्यालय सहित बडौदा और विजयपुर में कृषि उपज मंडी संचालित है। जबकि वीरपुर, कराहल और ढोढर में उप कृषि मंडियां संचालित हो रही है। लेकिन इन मंडियों में सुविधाओं के नाम पर स्थिति शून्य बनी हुई है। जिस कारण खामियाजा व्यापारी और किसान दोनों भुगतना पड रहा है। इसके अलावा मानपुर में भी उप कृषि मंडी मौजूद है। लेकिन इस मंडी में अभी तक खरीदी कार्य ही शुरू नहीं हो सका है। जिस कारण लाखो रुपए खर्च करके मानपुर में बनाई गई उप मंडी अनुपयोगी साबित हो रही है।

ढोढर की उप-मंडी बदहाल

विकासखंड श्योपुर के ग्राम ढोढर में उपमंडी संचालित है। ये भी श्योपुर कृषि उपज मंडी के अधीन है। लेकिन यहां भी सुविधाएं नगण्य है। स्थिति ये है कि यहां भी फसलों को बारिश से बचाने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं। इसके साथ ही किसानों और व्यापारियों के लिए पानी व छांव की सुविधा नहीं हैं। मंडी में एक पुराना गोदाम बना हुआ है, लेकिन वो क्षतिग्रस्त हो गया है।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)